Rights and Duties

When people come in contact as member of society, they have certain legal rights and duties towards one another. These rights and duties are regulated by the law prevalent in the society. It is well known that the main purpose of law is to protect human interests by regulating the conduct of individuals in the society. For the attainment of this objective, it's necessary that state should make use of its physical force for the enforcement of legal rights and punish those who violated rights.

It, therefore, follows that in all civilized societies law consists of those rules which regulate human conduct and it is the state which enforces the rights and duties created by such rules. The conception of right accordingly is of fundamental significance in modern legal theory because rights are indispensable for all civil societies and are recognized and enforced by the state.

अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties)

जब लोग समाज के सदस्य के रूप में एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनके बीच कुछ कानूनी अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य समाज में प्रचलित कानून द्वारा विनियमित (नियंत्रित) किए जाते हैं। यह सर्वविदित है कि कानून का मुख्य उद्देश्य मानव हितों की रक्षा करना है, जो समाज में व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करके प्राप्त किया जाता है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य अपने अधिकारों के प्रवर्तन (enforcement) के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करे तथा उन व्यक्तियों को दंडित करे जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि सभी सभ्य समाजों में कानून उन नियमों का समूह होता है जो मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं, और राज्य ही उन नियमों द्वारा उत्पन्न अधिकारों और कर्तव्यों को लागू करता है।

इस प्रकार, आधुनिक विधि सिद्धांत में "अधिकार" की अवधारणा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकार किसी भी सभ्य समाज के लिए अनिवार्य होते हैं और उन्हें राज्य द्वारा मान्यता एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है।

6.1 Definition of Right

According to Austin it's a faculty which resides in a determinate party or parties by virtue of a given law and which avails against a person. He observes 'a party has a right when another or others are bound or obliged by law to do or for bear towards or in regard to him.[1]

According to Vinogradoff 'Right is a range of action assigned to a particular will with in the social order established by law'

According to Inhering- it is a legally protected interest.

According to Holland- It's the capacity residing in one man of controlling with the assent and

assistance of the state the action of others.

According to Prof Patton - Prof Patton says that a legal right should be enforceable by legal process of state.

According Salmond Rights are interest recognized and protective by the rule of legal justice.[2]

6.1 अधिकार की परिभाषा (Definition of Right)

John Austin के अनुसार—

अधिकार एक ऐसी शक्ति (faculty) है जो किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों में विधि (law) के द्वारा निहित होती है और जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी होती है। उनके अनुसार, "किसी व्यक्ति के पास अधिकार तब होता है जब अन्य व्यक्ति कानून द्वारा उसके प्रति कुछ करने या न करने के लिए बाध्य होते हैं।"

Paul Vinogradoff के अनुसार—

"अधिकार वह क्रियाओं का क्षेत्र (range of action) है, जो किसी विशेष इच्छा (will) को कानून द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था के भीतर प्रदान किया जाता है।"

Rudolf von Jhering के अनुसार—

अधिकार एक विधिक रूप से संरक्षित हित (legally protected interest) है।

[1] John Austin proposed the 'command theory' of law, emphasizing sovereign authority and legal positivism.
[2] John Salmond defined jurisprudence as the science of the first principles of civil law

Thomas Erskine Holland के अनुसार—

अधिकार वह क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति राज्य की स्वीकृति और सहायता से दूसरों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है।

George Whitecross Paton के अनुसार—

कानूनी अधिकार वह है जिसे राज्य की विधिक प्रक्रिया द्वारा लागू (enforce) किया जा सके।

John Salmond के अनुसार—

अधिकार वे हित (interests) हैं जिन्हें विधिक न्याय के नियमों द्वारा मान्यता और संरक्षण प्रदान किया जाता है।

6.1.1 Elements of a legal Rights

1. **The subject** – Person to whom right is provided is subject. A legal right without a person cannot exist.
2. **Person of incidence –** Person who is bound to do the duty is person of incidence.

3. Subject matter of right- Subject matter, some right, omission or act is also an essential.

4 .Contents – Contents are essential.

5. Some title – Each and every legal right has a title.

Keeton has expressed a view that a right has only four elements and title is not included in this.

Salmon illustrates (The person of inherence, the person of incidence, content of the right, subject matter of right, Title of the right) above element of a legal right by citing an example that is , if a busy a piece of land from B.A. is the subject or owner of the right so required. The person bound by the co relative duty are persons in general because a right of this kind avails against the world at large. The contents of rights consist in non interference with the purchaser's exclusive use of the land. The object or the subject matter of right is the conveyance by which it was acquired from the former owner.

6.1.1 विधिक अधिकार के तत्व (Elements of a Legal Right)

विधिक अधिकार (Legal Right) **के निम्नलिखित मुख्य तत्व होते हैं—**

1. विषय (The Subject / Person of Inherence)

जिस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, उसे विषय (Subject) **कहा जाता है। किसी व्यक्ति के बिना कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं रह सकता।**

2. दायित्व वाला व्यक्ति (Person of Incidence)

वह व्यक्ति जो उस अधिकार के अनुरूप कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य होता है, उसे Person of Incidence **कहा जाता है।**

3. अधिकार का विषय-वस्तु (Subject Matter of Right)

अधिकार का विषय-वस्तु वह वस्तु, कार्य (act) **या परिहार (**omission) **होता है, जिस पर अधिकार लागू होता है। यह भी एक आवश्यक तत्व है।**

4. अधिकार की सामग्री (Contents)

अधिकार की सामग्री से तात्पर्य उन कार्यों या परिहारों से है, जिन्हें करने या न करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार के प्रयोग का स्वरूप दर्शाता है।

5. शीर्षक (Title)

प्रत्येक विधिक अधिकार का एक शीर्षक (Title) **होता है, अर्थात वह आधार या कारण जिसके द्वारा अधिकार प्राप्त किया जाता है, जैसे— क्रय (**purchase), **उत्तराधिकार (**inheritance) **आदि।**

George Whitecross Paton का मत—

उनके अनुसार विधिक अधिकार के केवल चार तत्व होते हैं और "Title" **को वे इसमें शामिल नहीं करते।**

John Salmond द्वारा उदाहरण—

सालमंड ने इन तत्वों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है—

यदि A ने B से भूमि का एक टुकड़ा खरीदा है, तो—

- **A अधिकार का विषय (**Subject) **या स्वामी है।**
- **इस अधिकार के अनुरूप कर्तव्य से बंधे व्यक्ति सामान्य रूप से सभी लोग हैं, क्योंकि यह अधिकार पूरे विश्व के विरुद्ध प्रभावी होता है।**
- **अधिकार की सामग्री (**Contents) **यह है कि कोई भी व्यक्ति उस भूमि के उपयोग में हस्तक्षेप न करे।**
- **अधिकार का विषय-वस्तु (**Subject Matter) **वह भूमि है।**
- **अधिकार का शीर्षक (**Title) **वह विक्रय (**sale/conveyance) **है, जिसके द्वारा यह अधिकार पूर्व स्वामी से प्राप्त हुआ।**

इस प्रकार, ये सभी तत्व मिलकर किसी विधिक अधिकार की पूर्ण संरचना को स्पष्ट करते हैं।

6.1.2 Theories of Right-

There are two basic theories of right

1. The will theory
2. The interest theory

1. The will theory -

This theory says that the purpose of law is to grant the individual to self expression of self-assertion. So rights emerge from the human will. According to Austin and Holland will is the main element of a right. In certain areas state could not interfere. So right is a will of people and the basis of right is the will of the individual.[3]

2. The Interest theory-

According to Ihering interest is the basis of right, and he defines legal rights as a legally protected interest. So right is an interest protected by law? People argued the right to protect their interest. According to Ihering right is interest and not will so there must be some interest for any legal right. And there is a right there will be duty

[3] John Austin proposed the 'command theory' of law, emphasizing sovereign authority and legal positivism.

also. These interest does not created by the state but they exist in the life of the community it self. State only chose some interest to protect him.

6.1.2 अधिकार के सिद्धांत (Theories of Right)

अधिकार के दो प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं—

1. इच्छा सिद्धांत (The Will Theory)
2. हित सिद्धांत (The Interest Theory)

---

1. इच्छा सिद्धांत (The Will Theory)

यह सिद्धांत कहता है कि कानून का उद्देश्य व्यक्ति को आत्म-अभिव्यक्ति (self-expression) और आत्म-प्रतिपादन (self-assertion) की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसलिए अधिकार मानव की इच्छा (will) से उत्पन्न होते हैं।

John Austin और Thomas Erskine Holland के अनुसार—
इच्छा (will) ही अधिकार का मुख्य तत्व है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होते हैं।

इस सिद्धांत के अनुसार—

- अधिकार व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है।
- अधिकार का आधार व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा (free will) है।

---

2. हित सिद्धांत (The Interest Theory)

यह सिद्धांत **Rudolf von Jhering** द्वारा प्रतिपादित किया गया है।

उनके अनुसार—

अधिकार का आधार "हित" (interest) है, और उन्होंने अधिकार को "विधि द्वारा संरक्षित हित" (legally protected interest) के रूप में परिभाषित किया है।

इस सिद्धांत के अनुसार—

- व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए अधिकारों का दावा करता है।
- जहाँ अधिकार होता है, वहाँ उसके साथ एक कर्तव्य (duty) भी होता है।
- हित समाज में स्वयं विद्यमान होते हैं, उन्हें राज्य उत्पन्न नहीं करता।
- राज्य केवल उन हितों को चुनता है जिन्हें वह कानूनी संरक्षण देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

इच्छा सिद्धांत अधिकार को व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से जोड़ता है, जबकि हित सिद्धांत अधिकार को व्यक्ति के हितों की रक्षा से संबंधित मानता है। दोनों सिद्धांत मिलकर अधिकार की व्यापक समझ प्रदान करते हैं।

6.1.3 Kinds of legal Rights

According to Salmond legal rights may be divided into eight kinds.[4]

1. Antecedent and Remedial Rights-

When a right exists independent of any other right and for its own sake it's an 'antecedent' right. When another right is joined to it (generally, in case of violation of the latter) then so joined right is called a Remedial right for example- A has a right that n o body should defame him. It is an antecedent right. If any person defames A, A has a right to receive damages from him. This is a 'remedial right'.

These rights are also called as 'primary' and secondary rights, principal and accessory rights. According to Pollack they may be called as subjective and adjective rights.

[4] John Salmond defined jurisprudence as the science of the first principles of civil law.

2. Perfect and Imperfect Right-

A 'perfect right' means a right which has a correlative duty that can be legally enforced. Generally when law recognizes a right, it prescribes a remedy also and when the right is violated. It enforces it. An 'imperfect right' is that right which, although recognized by law, is not enforceable, such as the claims barred by time. In such cases, the Limitation does not extinguish the right, but bars the remedy only. The claim is valid in other respects, but it cannot be enforced. Such cases may be considered as an exception to the rule **ubi jus ibi remedium (**when there is a right there is a remedy.)

Although an imperfect right gives no cause for action, its valid defense. If a time barred debt has been paid, it cannot be recovered. In a suit for recovery the imperfect right will work as a defense. A security given for a debt can be retained, although the debt is time barred on the ground of imperfect right. In certain conditions an imperfect right may become perfect.

For example- The part payment or only the acknowledgement of a time barred debt will make the right perfect.

3. Positive and Negative Rights-

A positive right is that right which has a correlative positive duty. In case of positive right the person having the right can compel the person upon whom the correlative duty is imposed to do some positive act. The scope of a negative right is only that the person having the right shall not be harmed. For law it is easier to enforce the negative than the positive right. Therefore, the number of positive rights is fewer than the negative rights.

4. Rights in Rem and Rights in Personam-

A right in personam is available against definite persons for example- A right to enjoy his garden and house is available against the whole world or the people in general. It's a right in ram. If a work for B under a contract his right to get remuneration is only against B and is a right in personam.

In rights in Rem the emphasis is on the res, but in rights in personam it's on the relationship between the parties which gave rise to the obligation. This distinction is closely connected with the classification of the rights I positive and negative.

Generally most of the rights in personam, are positive right and rights in Ram are mostly negative rights.

5. Proprietary and Personal Rights-

Proprietary right means a person's right in relation to his own property. Personal rights are rights relating to status and that arising out of contract. The aggregate of a person's proprietary rights constitutes his property or estate. The aggregate of a man's proprietary rights constitutes his property or estate. The aggregate of a man's personal rights constitutes his status.

According to Paton- Personal rights can be defined only as the residuary rights which remain after proprietary rights have been subtracted.

1. Proprietary rights are valuable, personal rights are not valuable. Proprietary rights are the element of a man's wealth. Personal rights 'are merely elements in his well being'
2. That proprietary rights are transferable, personal rights are not transferable.

6. Rights in Re Propria and Rights in Re Aliena-

Rights in Re propria mean the rights in one's own things. Rights in Re aliena are the rights in the things of others. The latter are called encumbrances also. Salmond defines the rights in Re aliena or encumbrance as one 'which limits or derogates from some more general rights belonging to some other person in respect of the same subject matter and all others are Jura in re propria the rights in re aliena or encumbrances arise when a person's right in his property becomes subject to another person's right in same property Such as the right of way over the land of another.[5]

7. Vested and Contingent Rights-

A right is a vested right when all the facts happening or not happening of which it is necessary to create or vest the right, have happened or not happened. If only some of such facts have occurred then the right is a contingent right. It would become vested when all the facts have occurred. A vested right creates an immediate interests. It's transferable and heritable. A contingent right does not create an

[5] John Salmond defined jurisprudence as the science of the first principles of civil law.

immediate interest, and it can be defeated when the required facts have not occurred.

8. Legal and Equitable Rights-

The rights recognized and enforced by the common law courts in England were known as 'legal rights' and the rights recognized and enforced by the chancery courts were known as equitable rights'. It's generally said that the equity was a gloss common law or, in other words, the equitable rights were mostly remedial rights. Thus chancery courts recognized a number of rights. Though after the passing of the judicature act, 1873 separate chancery courts have been abolished and now it is a division of the high court (chancery division) the distinction between the legal and the equitable rights continues.

In India there is no such division of rights as 'legal' and 'equitable'. There never had been two separate jurisdictions in this country.

Equitable rights were a creation of the English legal system.

6.1.3 विधिक अधिकारों के प्रकार (Kinds of Legal Rights)

John Salmond के अनुसार, विधिक अधिकारों को मुख्यतः आठ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है—

---

1. पूर्ववर्ती (Antecedent) और उपचारात्मक (Remedial) अधिकार

- **पूर्ववर्ती अधिकार** वह है जो स्वयं के लिए स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है।
- **उपचारात्मक अधिकार** वह है जो किसी अधिकार के उल्लंघन के बाद उत्पन्न होता है।

उदाहरण—

A का यह अधिकार कि कोई उसकी मानहानि न करे—पूर्ववर्ती अधिकार है। यदि कोई मानहानि करता है, तो हर्जाना पाने का अधिकार—उपचारात्मक अधिकार है।

इन्हें **Primary/Secondary**, **Principal/Accessory** भी कहा जाता है। **Frederick Pollock** ने इन्हें Subjective और Adjective rights कहा है।

---

2. पूर्ण (Perfect) और अपूर्ण (Imperfect) अधिकार

- **पूर्ण अधिकार** वह है जिसे कानून द्वारा लागू (enforce) किया जा सकता है।
- **अपूर्ण अधिकार** वह है जिसे कानून मान्यता तो देता है, पर लागू नहीं करता (जैसे—समय-सीमा से बाधित दावे)।

विशेष—

- Limitation remedy को समाप्त करती है, अधिकार को नहीं।
- आंशिक भुगतान या स्वीकारोक्ति से अपूर्ण अधिकार पूर्ण बन सकता है।

---

3. सकारात्मक (Positive) और नकारात्मक (Negative) अधिकार

- **सकारात्मक अधिकार**—जिसमें सामने वाले को कोई कार्य करना पड़ता है।
- **नकारात्मक अधिकार**—जिसमें केवल हस्तक्षेप न करने का दायित्व होता है।

नोट—कानून के लिए नकारात्मक अधिकार लागू करना आसान होता है।

---

4. Rights in Rem और Rights in Personam

- **Right in Rem**—पूरे विश्व के विरुद्ध लागू होता है (जैसे संपत्ति का अधिकार)।
- **Right in Personam**—केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होता है (जैसे अनुबंध से उत्पन्न अधिकार)।

---

5. स्वामित्व (Proprietary) और व्यक्तिगत (Personal) अधिकार

- **Proprietary अधिकार**—संपत्ति से संबंधित होते हैं।
- **Personal अधिकार**—व्यक्ति की स्थिति (status) या अनुबंध से संबंधित होते हैं।

George Whitecross Paton के अनुसार—

Personal rights वे शेष अधिकार हैं जो proprietary अधिकार हटाने के बाद बचते हैं।

अंतर—

- Proprietary अधिकार मूल्यवान व हस्तांतरणीय होते हैं।
- Personal अधिकार सामान्यतः न तो मूल्यवान होते हैं, न हस्तांतरणीय।

---

6. Rights in Re Propria और Rights in Re Aliena

- **Re Propria**—अपनी वस्तु पर अधिकार।
- **Re Aliena**—दूसरों की वस्तु पर अधिकार (Encumbrances)।

उदाहरण—दूसरे की भूमि पर रास्ते का अधिकार (Right of Way)।

---

7. निहित (Vested) और सशर्त (Contingent) अधिकार

- **Vested Right**—जब सभी आवश्यक तथ्य पूर्ण हो चुके हों; तत्काल हित उत्पन्न करता है।
- **Contingent Right**—जब कुछ शर्तें अभी पूरी होनी बाकी हों।

अंतर—

- Vested अधिकार हस्तांतरणीय और उत्तराधिकार योग्य होते हैं।
- Contingent अधिकार अनिश्चित होते हैं।

---

8. विधिक (Legal) और न्यायसंगत (Equitable) अधिकार

- **Legal Rights**—जो सामान्य न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- **Equitable Rights**—जो इंग्लैंड के चांसरी न्यायालयों द्वारा विकसित किए गए।

नोट—

- **Judicature Act 1873** के बाद दोनों में औपचारिक अंतर कम हो गया।
- भारत में इस प्रकार का पृथक विभाजन नहीं है।

निष्कर्ष

विधिक अधिकारों के ये प्रकार अधिकारों की प्रकृति, प्रभाव और प्रवर्तन को समझने में सहायता करते हैं और विधि के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Legal Rights v. Moral/Natural Rights-

- Legal rights are recognized by the state but natural rights do not have recognition.
- Leal rights are protected by legal justice but natural rights are protected by natural justice (moral).
- Violation of legal rights is a legal wrong but in case of natural right it's a moral wrong.
- Its respect is a legal duty and respect for moral right is a moral duty.

Legal Rights v. Fundamental Rights-

- Legal rights emerge from general laws but fundamental rights emerge from constitution itself.
- In violation of legal rights plaintiff can got to the court in hierarchal structure but in case of fundamental rights. He can go to Supreme Court directly.
- State is more responsible for fundamental rights than legal rights.
- Legal rights can abolish or change by a general legislative provision but fundamental rights can be amended by the parliament after a strong procedure and can not abolish as well as take away.
- Legal rights establish the relation between people/individuals but fundamental right is a concept relating to relation between state and individual.

- General legal right has a positive nature to do something but fundamental right is a negative concept which prohibits the state to do something.

Legal Rights बनाम Moral/Natural Rights (विधिक अधिकार बनाम नैतिक/प्राकृतिक अधिकार)

- **मान्यता (Recognition)**

विधिक अधिकार (Legal Rights) को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जबकि नैतिक/प्राकृतिक अधिकार (Moral/Natural Rights) को कानूनी मान्यता आवश्यक नहीं होती।

- **संरक्षण (Protection)**

विधिक अधिकारों की रक्षा विधिक न्याय (legal justice) द्वारा होती है, जबकि नैतिक अधिकारों की रक्षा नैतिकता (moral/natural justice) द्वारा होती है।

- **उल्लंघन (Violation)**

विधिक अधिकार का उल्लंघन एक **कानूनी गलत (legal wrong)** होता है, जबकि नैतिक अधिकार का उल्लंघन **नैतिक गलत (moral wrong)** होता है।

- **कर्तव्य (Duty)**

विधिक अधिकारों का सम्मान करना **कानूनी कर्तव्य** है, जबकि नैतिक अधिकारों का सम्मान करना **नैतिक कर्तव्य** है।

Legal Rights बनाम Fundamental Rights (विधिक अधिकार बनाम मौलिक अधिकार)

- **उत्पत्ति (Origin)**

विधिक अधिकार सामान्य कानूनों (statutes) से उत्पन्न होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार सीधे **Constitution of India** से प्राप्त होते हैं।

- **न्यायालय में प्रवर्तन (Enforcement)**

  विधिक अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति सामान्य न्यायालयों की श्रेणी (hierarchy) में जाता है, जबकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे **Supreme Court of India** में जा सकता है (अनुच्छेद 32)।

- **राज्य की जिम्मेदारी (State Responsibility)**

  मौलिक अधिकारों के संरक्षण में राज्य की जिम्मेदारी अधिक होती है, जबकि विधिक अधिकारों में अपेक्षाकृत कम।

- **परिवर्तन (Amendment/Change)**

  विधिक अधिकार सामान्य विधायी प्रक्रिया से बदले या समाप्त किए जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया से ही संभव है और उन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता।

- **संबंध (Relation)**

  विधिक अधिकार व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार मुख्यतः **राज्य और व्यक्ति** के बीच संबंध को नियंत्रित करते हैं।

- **स्वरूप (Nature)**

  सामान्य विधिक अधिकार प्रायः **सकारात्मक (positive)** होते हैं (कुछ करने का अधिकार), जबकि मौलिक अधिकार प्रायः **नकारात्मक (negative)** होते हैं (राज्य को कुछ करने से रोकते हैं)।

निष्कर्ष

विधिक, नैतिक और मौलिक अधिकारों के बीच यह अंतर हमें यह समझने में सहायता करता है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के अधिकार समाज और राज्य की व्यवस्था में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं।

6.2 Definition of Duties

Duty is bondage and every duty is a normative judgment. A duty is an act to do something bound by state to completion of right of another person. A duty contains the order to do or to do not something. According to Salmond duty is a legal duty because it is recognized by law. Violation of duty is a behavior against the will of the state. The main purpose of duty is to conserve the interest of the people.[6]

6.2 कर्तव्य की परिभाषा (Definition of Duties)

कर्तव्य (**Duty)** एक बंधन (**bondage)** है और प्रत्येक कर्तव्य एक मानक निर्णय (**normative judgment)** को दर्शाता है। कर्तव्य का अर्थ है—किसी कार्य को करना या न करना, जिसके लिए व्यक्ति कानून द्वारा बाध्य होता है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार की पूर्ति हो सके।

दूसरे शब्दों में, कर्तव्य वह है जिसमें राज्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने का आदेश देता है। यह अधिकार और कर्तव्य के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करता है—जहाँ अधिकार होता है, वहाँ उसके अनुरूप कर्तव्य भी होता है।

John Salmond के अनुसार—

कर्तव्य एक विधिक कर्तव्य (**legal duty)** है क्योंकि इसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।

कर्तव्य के मुख्य बिंदु—

- कर्तव्य कानून द्वारा मान्य और नियंत्रित होता है।
- कर्तव्य का उल्लंघन राज्य की इच्छा (**will of the state)** के विरुद्ध आचरण माना जाता है।
- कर्तव्य का पालन समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

[6] John Salmond defined jurisprudence as the science of the first principles of civil law.

निष्कर्ष

कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों के हितों (**interests)** की रक्षा करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है।

6.2.1 Classification of Duties-

1. Positive Duty-

It means to do something. It implies some act on a person to perform his duty. For example- if a person takes loan from another for a fixed time period after the time limit the borrower (loan taking person) has duty bound to return the payment. Same as in case of a contract both the parties are bound to complete their duty on their part due to a contract. In simple words positive duty encourage to a person to do something for prevention of legal of another person.

2. Negative duty-

It means do not something. It prohibits doing certain act which can curtail the legal rights of another person. So it's called negative duty. For example – Not to trespass, not to attack, do not make interference, not to defame are some concepts which called as negative duty because here law prohibits to do something.

3. Primary and Secondary duties

Primary duties which move as free, means not related to other duty. Not to commit an offence is a primary duty. Secondary duties are those which depend upon other duty.

6.2.1 कर्तव्यों का वर्गीकरण (Classification of Duties)

विधि में कर्तव्यों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है—

---

1. सकारात्मक कर्तव्य (Positive Duty)

सकारात्मक कर्तव्य का अर्थ है—कुछ करना। इसमें व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है।

उदाहरण—

- यदि कोई व्यक्ति ऋण लेता है, तो समय पूरा होने पर उसे वापस करना उसका कर्तव्य है।
- अनुबंध (**contract)** में दोनों पक्ष अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं।

सरल शब्दों में—

सकारात्मक कर्तव्य व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे दूसरे के अधिकार की पूर्ति हो सके।

---

2. नकारात्मक कर्तव्य (Negative Duty)

नकारात्मक कर्तव्य का अर्थ है—कुछ न करना। यह उन कार्यों को करने से रोकता है जो दूसरे के अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

उदाहरण—

- अतिक्रमण (**trespass)** न करना
- आक्रमण (**attack)** न करना
- हस्तक्षेप (**interference)** न करना
- मानहानि (**defamation)** न करना

सरल शब्दों में—

नकारात्मक कर्तव्य व्यक्ति को ऐसे कार्यों से रोकता है जो दूसरों के अधिकारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

---

3. प्राथमिक और द्वितीयक कर्तव्य (Primary and Secondary Duties)

- **प्राथमिक कर्तव्य (Primary Duty)—**

  यह स्वतंत्र (**independent)** कर्तव्य होता है, जो किसी अन्य कर्तव्य पर निर्भर नहीं होता।

  उदाहरण—अपराध न करना।

- **द्वितीयक कर्तव्य (Secondary Duty)—** यह किसी प्राथमिक कर्तव्य के उल्लंघन के बाद उत्पन्न होता है। **उदाहरण—**यदि किसी ने नुकसान पहुँचाया है, तो क्षतिपूर्ति (**compensation)** देना उसका द्वितीयक कर्तव्य है।

निष्कर्ष

कर्तव्यों का यह वर्गीकरण हमें यह समझने में सहायता करता है कि कानून किस प्रकार व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करता है और समाज में संतुलन बनाए रखता है।

6.3 Rights and Duties are co-relative-

Almost all the jurists agree on the point that rights and duties are necessarily co relative with each other in such a way that one cannot exists without the other. In other words, the existence of the one depends on the existence of the other as there can be no child without a father and no father without a child. A right is always against someone upon whom the correlative duty is imposed. In the same way a duty is always towards someone in whom the correlative right vests. There are some jurists who do not agree to this view.

Austin is one of them. He says that the duties may be divided into two kind's i.e.[7]

a. Absolute and
b. Relative again, Austin says that absolute duties are duties without a corresponding right. The duties which are always correlated with a right are called 'relative duties' according to Austin, there are four kinds of absolute duties.

1. Duties not regarding person (i.e. those owed to God and the lower animals)
2. Duties owed to persons indefinitely (i.e. towards the community)

[7] John Austin proposed the 'command theory' of law, emphasizing sovereign authority and legal positivism.

3. Self regarding duties.
4. Duties owed to the sovereign

The absolute duties enumerated by Austin are not duties in the legal sense or if they are duties at all, they are not absolute. The duty towards God is not a legal duty if it is not embodied in some statute. If it's embodied in a statute then it is the duty towards the state and not towards God. Certain duties imposed on individuals towards animals are in essence the duties towards the state or the owner of the animal and not towards the animal itself. The duties towards the community in general is nothing more than a bundle of duties towards each particular individual of the community and each individual has got a correlative right. Self regarding duties are also the duties towards the state because it's a part of the criminal law as an attempt to commit suicide.

So far as the fourth class of absolute duties, e.g. duties owed to the sovereign' is concerned, they are based on his definition of law and his theory about state and sovereignty. If we regard the relationship between the state and the individual as the right duty relationship where is this political superior? In recognizing any other political superior, Austin's definition of the sovereign would be exploded. The sovereign has the power to change the law at any time. Therefore the relation ship between the state and the citizen cannot be termed as right duty relationship. [83]

Thus, the view taken by Austin is not a correct one though it's admitted that the relationship between the state and the citizen does not stand on the same footing as the relationship between a citizen and a citizen. It depends more on the nature of the state than on anything else. In democratic countries, a citizen has rights against the state. [84]

Itis absolutely true that rights and duties are correlated to they are two aspect of the same coin one cannot exist without other just like this Ason cannot exist without father. Where there is right, there will be absolutely duty. It is clear by eminent jurist Salmond. Keeton, Holland they were strictly supported of this theory an it is also clear by the definition of rights and duties that both are related and complementary to each other. [85]

In the land mark judgment given by Hon'ble S.C it is decided that Rights and duties are correlated to each other if anybody have a right then absolutely any other person will have a duty for example – fundamental rights.

6.3 अधिकार और कर्तव्य परस्पर सह-संबंधित हैं (Rights and Duties are Co-relative)

अधिकांश विधिवेत्ताओं (jurists) का यह मत है कि अधिकार (Rights) और कर्तव्य (Duties) एक-दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। अर्थात् एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे बिना पिता के पुत्र नहीं हो सकता और बिना पुत्र के पिता नहीं—उसी प्रकार बिना कर्तव्य के अधिकार और बिना अधिकार के कर्तव्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

- प्रत्येक **अधिकार** किसी न किसी व्यक्ति के विरुद्ध होता है, जिस पर उसका संबंधित **कर्तव्य** लागू होता है।
- उसी प्रकार प्रत्येक **कर्तव्य** किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति होता है, जिसमें संबंधित **अधिकार** निहित होता है।

Austin का दृष्टिकोण (विरोधी मत)

John Austin इस सिद्धांत से पूर्णतः सहमत नहीं थे। उन्होंने कर्तव्यों को दो भागों में विभाजित किया—

1. **Absolute Duties (निरपेक्ष कर्तव्य)**
2. **Relative Duties (सापेक्ष कर्तव्य)**

- **Relative Duties** वे हैं जो किसी अधिकार से जुड़े होते हैं।
- **Absolute Duties** वे हैं जिनका कोई संबंधित अधिकार नहीं होता।

Austin के अनुसार Absolute Duties के चार प्रकार हैं—

1. ईश्वर एवं पशुओं के प्रति कर्तव्य
2. समाज के प्रति सामान्य कर्तव्य
3. स्वयं के प्रति कर्तव्य (Self-regarding duties)
4. संप्रभु (Sovereign) के प्रति कर्तव्य

Austin के सिद्धांत की आलोचना (Criticism)

Austin द्वारा बताए गए “Absolute Duties” को पूर्णतः विधिक कर्तव्य नहीं माना जा सकता—

- **ईश्वर के प्रति कर्तव्य**—यदि कानून में नहीं है, तो यह विधिक कर्तव्य नहीं है; और यदि कानून में है, तो यह राज्य के प्रति कर्तव्य बन जाता है।
- **पशुओं के प्रति कर्तव्य**—वास्तव में ये राज्य या पशु के स्वामी के प्रति कर्तव्य होते हैं।
- **समाज के प्रति कर्तव्य**—ये वास्तव में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कर्तव्यों का समूह हैं, जिनके साथ अधिकार जुड़े होते हैं।
- **स्वयं के प्रति कर्तव्य**—ये भी राज्य के प्रति कर्तव्य माने जाते हैं (जैसे आत्महत्या का प्रयास दंडनीय होना)।
- **संप्रभु के प्रति कर्तव्य**—यह Austin के राज्य और संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यवहार में पूर्णतः उचित नहीं माना गया।

समर्थन (Supporting View)

John Salmond, Thomas Erskine Holland और George Whitecross Paton ने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि—

अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।

न्यायालय का दृष्टिकोण

भारत में **Supreme Court of India** ने भी अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में यह माना है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है, तो अवश्य ही किसी अन्य व्यक्ति पर उसके अनुरूप कर्तव्य होगा।

उदाहरण—

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) के साथ राज्य पर यह कर्तव्य होता है कि वह उन अधिकारों का संरक्षण करे।

निष्कर्ष

यह पूर्णतः सत्य है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर सह-संबंधित (co-relative) हैं। वे एक ही व्यवस्था के दो पक्ष हैं और समाज में संतुलन तथा न्याय बनाए रखने के लिए दोनों का साथ-साथ होना आवश्यक है।

**********==========**********==========**********